मध्य प्रदेश की चितरंगी में कुष्ठ रोग का प्रकोप

1749. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में जिला सीधी के विकास खण्ड चितरंगी में रहने वाले लोगों को कुष्ठ रोग का प्रकोप हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के उपचार हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Eye-care Treatment Available in Rajasthan and Orissa

1750. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that over 12 million people, who could be readily cured by simple surgery, continued to be blind in India as reported in the Hindustan Times dated 21st February, 1997;

(b) if so, what type of eye care treatment is available in rural areas of States like Rajasthan and Orissa;

(c) whether at the recently held conference of 55th All India Opthalmological Society in New Delhi, any concrate programme for eradication of this problem in rural areas of the country was chalked out; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) According to the National Survey conducted in 1986—89, there were about 12 million blind persons in the country, 80% of which were due to cataract which can be cured by simple surgery.

(b) Cataract patients are treated free of cost through Cataract Surgery performed in eye camps, organised by Government and Non-Government Organisations.

(c) and (d) The organisers of the conference have not informed government of any such programme.

मध्य प्रदेश में सरकारी और निजी चिकित्सा कालेज

1751. **श्री अजीत जोगी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में कितने-कितने सरकारी और निजी चिकित्सा कालेज हैं;

(ख) क्या राज्यों में मेडिकल कालेज खोलने के लिए राज्य सरकार/गैर-सरकारी संस्थानों ने सरकार से अनुमति ले ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) जिन राज्यों में मेडिकल कालेज की संख्या कम है वहां पर निजी मेडिकल कालेज खोलने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) देश में सरकारी तथा निजी चिकित्सा कालेजों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त चिकित्सा कालेजों की संख्या को विवरण-II में दर्शाया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के अनुसार, देश में निजी चिकित्सा कालेज खोलने पर किसी प्रकार का प्रोत्साहन देने का प्रावधान नहीं है।

विवरण-I

देश में सरकारी और निजी चिकित्सा कालेज

	सरकारी कालेज	निजी कालेज
1. आन्ध्र प्रदेश	9	1
2. असम	3	—

3. बिहार	9	4
4. गोवा	1	—
5. गुजरात	7	1
6. हरियाणा	1	1
7. हिमाचल प्रदेश	1	—
8. जम्मू व कश्मीर	2	2
9. कर्नाटक	4	15
10. केरल	5	1
11. मध्य प्रदेश	6	—
12. महाराष्ट्र	15	18
13. मणिपुर	—	1
14. उड़ीसा	3	—
15. पंजाब	3	2
16. राजस्थान	6	—
17. तमिलनाडु	10	6
18. त्रिपुरा	—	1
19. उत्तर प्रदेश	9	2
20. पश्चिम बंगाल	7	—
21. दिल्ली	4	—
22. पांडिचेरी	1	1
23. चंडीगढ़	1	—
योग	107	56

कुल योग: 163 चिकित्सा कालेज

विवरण-II

केन्द्र सरकार की अनुमति से स्थापित किए जाने वाले चिकित्सा कालेजों की सूची

क्रमांक	चिकित्सा कालेज का नाम
निजी कालेज	
1.	एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज, साइन्सेज, पारियाराम, कन्नूर, केरल।
2.	महाराष्ट्र ऐकेडेमी मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च, पुणे, धावेड़, पुणे।
3.	आचार्य श्री चन्द्र कालेज, आफ मेडिकल साइन्सेज एंड हास्पिटल, गांधी नगर, जम्मू तवी, जम्मू एंड कश्मीर।
4.	पी० वी० नर्रासम्ह राव मेडिकल कालेज, जोलीग्रांट, देहरादून।
5.	डा० डी० वाई० पाटिल मेडिकल कालेज फार वूमेन, पिम्परी, पुणे।
6.	सन्तोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद।
7.	विनायक मिशन मेडिकल कालेज, सेलम।
8.	विनायक मिशन मेडिकल कालेज, करियाकल, पांडिचेरी।
सरकारी कालेज:	
9.	मेडिकल कालेज भावनगर।
10.	मेडिकल कालेज, राजकोट।

Privatisation of Electronic Media

1752. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government propose to privatise the electronic media;

(b) if so, the details thereof with background;

(c) whether these proposals provide for uplinking facilities to foreign T.V. Channels;

(d) whether these proposals also include foreign equity in Indian T.V. companies and radio broadcast services;

(e) whether some objectives are likely to be achieved with such moves of privatisation; and

(f) if so, details thereof and if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) and (b) Government intends to introduce a bill in Parliament which would seek to permit the entry of private sector in the field of broadcasting.

(c) to (f) The issues of permitting uplinking facility from Indian soil and allowing foreign equity in broadcasting companies are secondary to the question of permitting private broadcasting from within the country. The proposed